

ऐसी दशा में मैं संचार मंत्री का ध्यान टेलीफोन कुव्यवस्था की ओर आकर्षित करते हुए अपील करता हूँ कि इस जनपद में टेलीफोन में सुधार लाया जाए और जो भी कमी हो उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। जिससे जिले में टेलीफोन व्यवस्था ठीक हो सके और जनता में फैला अमंतोष दूर हो सके।

(ii) NEED TO RESTORE THE DESERT DEVELOPMENT SCHEME IN KARGIL DISTRICT OF LADAKH

SHRI P. NAMGYAL (Ladakh) : The Len and Kargil districts of Ladakh in Jammu and Kashmir State were included under the cold desert programmes ever since the said scheme come into existence. Suddenly last year, Government of India withdrew the scheme from parts of Kargil district on the basis of a task force's reports. It appeared that the so-called task force had based its report arbitrarily on the excuse of higher rain and snow-fall in Kargil area, which is contrary to the factual position. No doubt, during the winter, parts of Kargil district receive very heavy snow-fall, but during summer and particularly during the critical forming period, the snow gets exhausted much before the maturity period of the main crops. Many schemes and measures taken in hand under the Desert Development Programme in Kargil district for conservation of water and snow are lying incomplete, due to withdrawal of the said scheme.

I, therefore, urge upon the Government to restore the desert development scheme in the whole district of Kargil in the Ladakh region.

(iii) NEED FOR PROVIDING STOPPAGE OF THE PROPOSED SANCHI EXPRESS TRAIN AT VIDISHA AND ALSO RESERVATION QUOTA FOR VIDISHA

SHRI PRATAP BHANU SHARMA (Vidisha) : The Government is proposing to run Sanchi Express train Originating from New Delhi and going to Indore VIA Bhopal. It would be a great boon to the People of

Central India, especially Western Madhya Pradesh, connecting them to the capital of the country by a fast train.

It would also fulfil a long-standing need of a fast train between Indore and Bhopal, where the Major traffic has to move by road so far. I would appreciate if the new train is started by the 2nd October 1983 because the Railway Minister had recently announced that Sanchi Express shall be started shortly. I would also like to place certain expectations of the public for consideration by the Ministry :

1. The Sanchi Express train timings should be adjusted in such a way that it has not only convenient starting and arrival timings at its final destination, but also at Bhopal, the State capital.
2. The train should have a stop at Sanchi and Vidhisha, the historical towns that have given this train a name, in the first place.
3. There should be a reservation quota at Vidhisha for at least 12 to 15 berths in each direction.

(iv) NEED TO DECLARE SUPPORT PRICE OF WHEAT AT RS. 200/- PER QUINTAL BEFORE SOWING SEASON

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : हम देश की राष्ट्रीय आय कृषि उत्पादन से अधिक बढ़ा सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ने से देश की अस्सी प्रतिशत जनता किसान मजदूर को तो लाभ होगा ही, व्यापारियों, उद्योगपतियों और नौकरी करने वालों को भी लाभ होगा। जिस प्रदेश में कृषि उत्पादन अधिक होता है वहां की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय दो हजार रुपये से अधिक है तो बिहार में 750 रुपये है। पंजाब में बेरोजगारी नहीं, भिखारी नहीं, अन्य प्रदेशों में मजदूरी को नहीं जाते और स्वस्थ लड़के सेना को भी अधिक देते हैं। कृषि में पिछड़े हुए प्रदेशों की

स्थिति इसके विपरीत है। गांवों, कस्बों और शहरों की स्थिति भी कृषि-उत्पादन अधिक करने वाले प्रदेशों की अच्छी है। स्कूल और कालेज भी वहीं अधिक हैं। हमारे देश में कृषि उत्पादन बढ़ाना जनता की सर्वांगीण उन्नति का साधन है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने का सबसे सुगम तरीका उत्पादन का उचित मूल्य मिलना है। अब के किसानों के गेहूं का सरकार ने मूल्य कम नियत किया। कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की लागत 211 रुपये प्रति क्विंटल बताई थी। मूल्य नियत किया 151 रुपये।

किसान विचार कर रहा है कि गेहूं के स्थान पर उन फसलों को बोए जिन का मूल्य अधिक मिलता है। गेहूं का उत्पादन कम होने से हमें गेहूं का बाहर से आयात करना पड़ेगा। राष्ट्र की प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों कम होगी। कृषि मंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकते। अतः माननीया प्रधान मंत्री से प्रार्थना है कि गेहूं के मूल्य की गेहूं की बुआई से पहले घोषणा कर दें और वह 200 रुपये प्रति क्विंटल से कम नहीं होना चाहिये।

15.05 hrs.

[SHRI R.S. SPARROW : *in the Chair*]

(v) TRANSPORT ARRANGEMENTS IN THE HILLY REGIONS

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में परिवहन व्यवस्था की वर्तमान स्थिति अत्यधिक असन्तोषजनक है। नए मोटर मार्गों के खुलने से जहां अधिक बसों की मांग है, वहीं पुरानी जर्जर बसों के चलने से बस दुर्घटनाएं आम बात हो गई हैं। इस क्षेत्र के पिथौरागढ़ जनपद में विगत दो वर्षों के अन्तराल में 200 से अधिक व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने से अकाल

काल-कवलित हुए हैं। कुछ ही दिनों पूर्व यहां एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 26 व्यक्ति मरे हैं। इस सबके फलस्वरूप यहाँ भयंकर असन्तोष व रोष व्याप्त है। केन्द्रीय परिवहन अधिकरण को शीघ्र निम्न कदम उठाने के लिए राज्य के परिवहन एवं सार्वजनिक निर्माण विभागों तथा सीमा सड़क संगठन के लोगों को सलाह देनी चाहिए :—

1. इस क्षेत्र के समस्त मोटर मार्गों पर राज्य परिवहन निगम तथा प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित बस सेवाओं को समानान्तर रूप से चलने देना की अनुमति राज्य सरकार को देनी चाहिये। प्रतियोगिता के कारण दोनों संगठन अच्छी सेवा उपलब्ध करवाने का चेष्टा करेंगे।
2. पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे चैसिस की बसें चलाई जानी चाहियें।
3. इन क्षेत्रों में किसी भी ऐसी बस को नहीं चलाया जाना चाहिये जो कि 3 लाख किलोमीटर चल चुकी हो।
4. यहाँ प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर बस-डिपो व वर्कशाप खोले जाने चाहियें।
5. पिथौरागढ़ जैसे सीमान्त जनपद में क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्यालय शीघ्र खोला जाना चाहिये।
6. सार्वजनिक निर्माण विभाग और वाडर रोड संगठन को कहा जाना चाहिये कि वे वर्तमान मोटर मार्गों को और अधिक चौड़ा व सुविधायुक्त बनावे।
7. इन क्षेत्रों में चालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं उनकी शारीरिक स्वस्थता बनी रहे, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये।